(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) No, Sir. The subject 'prisons' being a State subject is administered by the State Government under their own Rules, Regulations and prison manuals.

झूठे जाति प्रमाण पत्र के लिए पैनल द्वारा गुजरात पर अभ्यारोपण

2970. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 दिसम्बर, 1994 को दैनिक टेलीग्राफ में प्रकाशित "पैनल इंडिक्ट्स गुजरात फॉर फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट्स" शीर्षक के समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुजरात राज्य में बड़ी संख्या में झूठे अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र जारी किये है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां । तथापि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार इसने गुजरात सरकार को झूठे जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए केवल सचेत किया है ।

(ख) और (ग) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के प्राधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास निहित नहीं है और इसलिए आयोग द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रश्न नही उठता।

महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकार

2971. **श्री सुशील कुमार सम्भाजीराव शिन्दे :**
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किये गये उपायों की तरह महिलाओं को पर्याप्त संपत्ति अधिकार देने सहित अन्य अधिकार देने और नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के संबंध मे व्यापक उपाय शुरू करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं को पर्याप्त संपत्ति अधिकार तथा नौकरियों में आरक्षण सहित शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए किए गए व्यापक उपाय के ब्यौरे प्राप्त करके उसकी जांच की जाएगी तथा उसके बाद सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा ।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग

2972. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1994 की तारीख को अनुसूचित जाति के कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं ;

(ख) सरकार द्वारा इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1991 की जनगणना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुमानित आंकड़ नही प्रदान करती है । फिर भी, नवीनतम उपलब्ध सूचना वर्ष 1987-88 से संबंधित है, और जिसके अनुसार यह अनुमान है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित 41.47% अनुमानित जनसंख्या उस वर्ष में गरीबी की रेखा से नीचे थी ।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए समाज के इस वंचित वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक नई नीति छठी योजना से शामिल की गई है जिसे निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है :—

(1) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना;

(2) विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता;

(3) राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगमों की स्थापना;

(4) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम;

(5) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (केन्द्रीय प्रायोजित);

(6) अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति ;

(7) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित) ;

(8) पुस्तक बैंक (केन्द्रीय प्रायोजित);

(9) लड़कियों के लिए होस्टल (केन्द्रीय प्रायोजित);

(10) लड़कों के लिए होस्टल (केन्द्रीय प्रायोजित);

(11) कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) (केन्द्रीय प्रायोजित);